तापमान

भोपाल	23.0°	29.0°
इंदौर	22.0°	29.0°
जबलपुर	24.0°	30.0°
ग्वालियर	25.0°	32.0°
सागर	23.0°	29.0°

नईदुनिया

वर्ष- 80
(भोपाल: वर्ष 41 अंक 236, पृष्ठ 12)
आषाढ़, शुक्ल एकादशी संवत् 2083
शनिवार, 25 जुलाई 2026
कीमत: 3:00 रुपये

www.naiduniaonline.com | भोपाल संस्करण | भोपाल एवं सागर से एकसाथ प्रकाशित

राजधानी... संतों की वाणी जीवन को सही दिशा देती ...

व्यापार... चांदी 2,924 रुपये और सोना 1,848 रुपये सस्ता, दोनों ...

खेल... अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन सहित सबसे अधिक रन...

देश-विदेश... नेपाल में न्यायपालिका की स्वतंत्रता...

खास-खबरें

अदालती कार्यवाही के प्रसारण पर रोक

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सामाजिक माध्यमों पर अदालती कार्यवाही के वीडियो साझा करने पर अंतरिम रोक लगा दी। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अदालती कार्यवाही की समाचार रिपोर्टिंग पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी और समाचार माध्यम पूर्व की तरह कार्यवाही का प्रकाशन एवं प्रसारण कर सकेंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने अदालती कार्यवाही के प्रत्यक्ष प्रसारण तथा उसके वीडियो सामाजिक माध्यमों पर साझा किए जाने पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया।

पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, दो की मौत

नईदुनिया ब्यूरो, सहारनपुर: सहारनपुर जिले में शुक्रवार शाम पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि ठेकेदार सहित दो लोग लापता बताए जा रहे हैं। विस्फोट इतना तेज था कि मृतकों के शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए। एक शव फैक्ट्री से लगभग 500 मीटर दूर खेत के किनारे मिला। घटनास्थल की स्थिति को देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, धमाके की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के क्षेत्रों में दहशत फैल गई। विस्फोट के बाद स्थानीय लोग तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन तथा अग्निशमन विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। हादसे में फैक्ट्री का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना गंगोह थाना क्षेत्र के नया गांव में हुई।

वांगचुक का अनशन समाप्त कराने में तन्खा ने की मध्यस्थता

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल समाप्त कराने को लेकर विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने सरकार और वांगचुक के बीच गतिरोध समाप्त कराने में मध्यस्थ की भूमिका निभाई। तीन दिन तक पर्दे के पीछे बातचीत चली, जिसके बाद सहमति बनी। अनशन समाप्त होने के बाद वांगचुक ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिला। उनके लिए छात्रों पर कार्रवाई रुकवाना सबसे महत्वपूर्ण था।

अमेरिका को अब 15 नहीं 10 प्रतिशत टैरिफ देगा भारत

प्रस्तावित टैरिफ में भारत को मिली 5 प्रतिशत की राहत, श्रम मानकों में सुधार से अमेरिका खुश

वॉशिंगटन, एजेंसी : अमेरिका ने शुक्रवार से भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लागू कियाा है। ट्रम्प प्रशासन द्वारा लगाया गया 15 प्रतिशत का अस्थायी वैश्विक टैरिफ समाप्त हो गया। उसके स्थान पर अब नया स्थायी 10 प्रतिशत शुल्क प्रभावी हो गया है। प्रारंभ में भारत पर 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन भारत सरकार द्वारा श्रम मानकों और आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी से जुड़े कुछ नीतिगत सुधार किए जाने तथा दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत के बाद इसे घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया।

श्रम आधारित उत्पादों में सुधार आया

अमेरिका का कहना है कि भारत ने श्रमिक अधिकारों की निगरानी और आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए हैं। हालांकि 10 प्रतिशत शुल्क लागू रहने का अर्थ यह भी है कि अमेरिका अभी श्रम मानकों के प्रभावी पालन को लेकर और सुधार की अपेक्षा रखता है। अमेरिका ने 17 देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। भारत, ब्रिटेन, कनाडा, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मेक्सिको, पाकिस्तान और श्रीलंका को 10 प्रतिशत शुल्क वाले समूह में रखा गया है। अमेरिका का कहना है कि इन देशों ने जबरन श्रम से निर्मित वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने अथवा उससे संबंधित सुधारात्मक कदम उठाए हैं। जबकि 43 देशों पर 12.5 प्रतिशत शुल्क लागू किया गया है। यह कार्रवाई अमेरिका के व्यापार अधिनियम-1974 की धारा 301 के तहत जबरन श्रम से निर्मित वस्तुओं को लेकर की गई है।

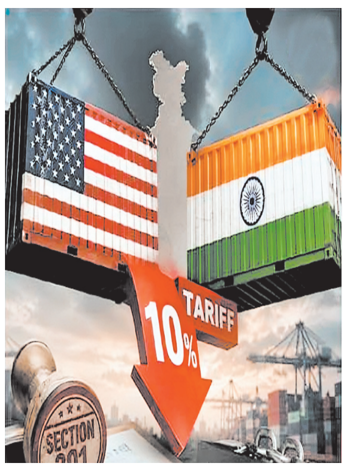

कपड़ा-आभूषण बाजार को लाभ की उम्मीद

भारत अमेरिका का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। ऐसे में टैरिफ कम होने से उन क्षेत्रों को लाभ हो सकता है, जिनकी निर्भरता अमेरिकी बाजार पर अधिक है। इनमें वस्त्र एवं परिधान, रत्न एवं आभूषण, चमड़ा उत्पाद, कृषि एवं खाद्य उत्पाद, अभियांत्रिकी उत्पाद, रसायन तथा कुछ विनिर्मित वस्तुएं शामिल हैं। अतिरिक्त शुल्क लगने से भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में महंगे हो सकते हैं, जिससे निर्यातकों पर कीमतें कम करने का दबाव बढ़ सकता है।

ईरान पर सबसे बड़ा हमला करेंगे: ट्रम्प

ईरान बोला- भारी कीमत चुकाना पड़ेगी

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन, एजेंसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर बड़े सैन्य हमले की तैयारी कर चुका है और अब केवल अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान ने अभी तक पर्याप्त नुकसान नहीं झेला है। ट्रम्प के इस बयान के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने अमेरिकी बयान पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए कड़ी चेतावनी दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि यदि अमेरिका ने हमले जारी रखे तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि संघर्ष समाप्त करने का रास्ता सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि बातचीत और कूटनीतिक समाधान है। इस बीच ब्रिटेन ने भी अपनी सेना को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर उसकी सेना देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। इससे पहले ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने चेतावनी दी थी कि यदि अमेरिका ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों का उपयोग करता है तो उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है।

विधेयक संसद में 27 जुलाई को होगा प्रस्तुत, सरकार ने किया कई सुधारों का दावा

पेपर लीक संशोधन बिल कैबिनेट में मंजूर

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: पेपर लीक संशोधन विधेयक को शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई। सूत्रों के अनुसार अब यह विधेयक सोमवार, 27 जुलाई को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी।

मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेपर लीक संशोधन विधेयक पर कोई टिप्पणी नहीं की। मीडिया के

प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने केवल इतना कहा कि इस विषय पर बाद में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने हल्के अंदाज में इतना अवश्य कहा कि आज कोई पेपर लीक नहीं हो रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात जारी वीडियो संदेश में कहा था कि पेपर लीक संशोधन विधेयक पर मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद इसे संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक लाखों विद्यार्थियों और उनके परिवारों के लिए अत्यंत पीड़ादायक विषय है। सरकार ने पिछले ढाई महीनों में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए हैं तथा कम समय में 22 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा कराकर परिणाम भी घोषित किया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। यह पूरा मामला तीन मई को हुई नीट स्नातक परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक से जुड़ा है। मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रहा है। महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली सहित कई राज्यों में जांच के दौरान अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और शीघ्र ही आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

सरकार और सीजेपी के बीच वार्ता, निर्णय आज संभव, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग बरकरार

नई दिल्ली: परीक्षा विवाद को लेकर शुक्रवार को दिल्ली स्थित संविधान क्लब में सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह, जबकि सीजेपी की ओर से सौरभ दास और आशुतोष रांका शामिल हुए। बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने आत्महत्या करने वाले नीट अभ्यर्थियों के परिजनों को मुआवजा देने तथा आंदोलनकारियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण वापस लेने पर सहमति जताई है। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने बताया कि लगभग दो घंटे चली बैठक में सीजेपी ने सरकार के समक्ष तीन प्रमुख मांगें और परीक्षा व्यवस्था में सुधार से जुड़े पांच सुझाव प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि इन मांगों पर विचार करने के लिए सरकार ने शनिवार तक का समय मांगा है। सरकार ने सीजेपी के प्रतिनिधियों को शनिवार अपराह्न साढ़े तीन बजे फिर से बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। सीजेपी ने कहा कि यदि अगले दो-तीन दिनों में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है तो वह फिर से बड़े स्तर पर मार्च निकाल सकती है।

राहुल ने घायल छात्र के घाव दिखाए

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपने आवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रदर्शन के दौरान घायल एक छात्र को साथ लाकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री की वजह से हजारों छात्र सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए हैं। राहुल गांधी ने छात्र के हाथ, पीठ और छाती पर लगे घाव दिखाते हुए दावा किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान वह पैलेट गन से घायल हुआ था।

सीजेआई ने मीडिया की रिपोर्टों को बताया गैर जिम्मेदार, केंद्र से जवाब-तलब

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि उन्होंने सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज से संबंधित किसी मामले की सुनवाई से इन्कार नहीं किया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में कोई रिट याचिका दायर ही नहीं की गई थी। मुख्य न्यायाधीश ने उन मीडिया रिपोर्टों को गैर जिम्मेदार बताया, जिनमें सुनवाई से इन्कार करने का दावा किया गया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय में एक भी पृष्ठ दाखिल नहीं हुआ था, केवल एक प्रतिनिधित्व भेजा गया था। नीट परीक्षा के

प्रश्नपत्र लीक मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से परीक्षा प्रणाली को स्थायी, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। न्यायालय ने कहा कि तदर्थ व्यवस्थाओं से समस्याएं पैदा हुई हैं। केंद्र की ओर से महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि सरकार शीघ्र विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी तथा छात्रों के भविष्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों से आगे बढ़कर कार्य कर रही है।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारी बर्खास्त

प्रश्नपत्र लीक प्रकरण में कार्रवाई तेज, आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होंगे

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: नीट प्रश्नपत्र लीक प्रकरण में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 47 अधिकारियों की सेवा समाप्त कर दी है। अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किए जाएंगे। बताया गया है कि एजेंसी में व्यापक सुधार की प्रक्रिया के तहत यह कार्रवाई की गई है तथा आने वाले समय में और भी कदम उठाए जाएंगे।

इससे एक दिन पहले केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के दो सचिवों में भी बदलाव किया था। अधिकारियों के अनुसार, परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से लगातार प्रशासनिक सुधार किए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश के लगभग 20 घंटे के भीतर यह कार्रवाई की गई। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा था कि प्रश्नपत्र लीक लाखों

विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक विषय है। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई महीनों में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और उन्हें जेल भेजा गया है। साथ ही विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष प्रभावित न हो, इसके लिए कम समय में 22 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा कराई गई। उन्होंने त्वरित न्यायालय स्थापित करने के निर्देश दिए जाने की भी जानकारी दी।

प्रश्नपत्र लीक प्रकरण की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रहा है। जांच के दौरान महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली सहित कई राज्यों में कार्रवाई की गई है। अब तक 13 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले में आरोपपत्र शीघ्र प्रस्तुत किए जाने की संभावना जताई गई है।

जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में शामिल 216 लोगों का मिला आपराधिक रिकॉर्ड

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में शामिल 216 ऐसे लोगों की पहचान की गई है, जिनका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पुलिस के अनुसार, चेहरा पहचान प्रणाली के माध्यम से सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित सामग्री और निगरानी कैमरों के चित्रों की जांच के दौरान इन लोगों की पहचान हुई। पुलिस ने बताया कि इनमें पश्चिमी, उत्तर-पूर्वी, दक्षिणी तथा अन्य जिलों के लोग शामिल हैं। मामले की जांच जारी है।

प्रदेश के चार महानगरों में स्थापित होंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट : डॉ. यादव

मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि अंतरित की, पर्यटन और रोजगार बढ़ाने पर बल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं की शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा के अनुरूप मध्यप्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में भी त्वरित न्यायालय प्रारंभ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष पन्ना चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण किया जाएगा, जिससे नीट अभ्यर्थियों को चिकित्सक बनने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री पन्ना में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 35 लाख से अधिक हितग्राहियों को लगभग 210 करोड़ रुपये की राशि एक साथ अंतरित की। साथ ही विभिन्न विभागों की योजनाओं के हितग्राहियों तथा आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने 184.83 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया। इनमें गुन्नौर और पवई में 74 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले दो सांदीपनि विद्यालय भी शामिल हैं। उन्होंने पन्ना के बृहस्पति कुंड में लगभग आठ करोड़ रुपये की लागत से निर्मित कांच के फर्श वाले दर्शनीय स्थल और अन्य विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में पर्यटन को नई पहचान मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने वाली योजना है और इससे किसानों की समृद्धि बढ़ेगी। उन्होंने परियोजना से प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा देने का भरोसा भी दिलाया।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में पुलिस विभाग में लगभग दस हजार नए पद स्वीकृत किए गए हैं तथा एक लाख से अधिक शासकीय पदों पर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री ने पर्यटन, कृषि, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन और औद्योगिक विकास के माध्यम से रोजगार बढ़ाने पर भी जोर दिया।

चलती टैक्सी पर चट्टान गिरने से 13 लोगों की मौत

भारी बारिश और भूस्खलन से कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले में शुक्रवार को उदयपुर-किलाड़ मार्ग पर कडू नाला के पास भूस्खलन हो गया। इस दौरान चलती टाटा सूमो टैक्सी पर अचानक चट्टानें गिर पड़ीं। वाहन में 15 लोग सवार थे, जिनमें से 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया।

देश के कई राज्यों में लगातार हो रही भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हो गया है। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन से बड़ा हादसा हुआ, जबकि गुजरात में बाढ़ जैसे

हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख नदियां उफान पर हैं और राजस्थान के कई जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वलसाड जिले के उमरगाम तालुका में 16 घंटे के दौरान 43 इंच वर्षा दर्ज की गई, जिससे निचले क्षेत्रों में व्यापक जलभराव हो गया। नवसारी जिले में बाढ़ में फंसे लोगों को हेलिकॉप्टर की सहायता से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अहमदाबाद और सूरत सहित कई शहरों में सड़कों तथा निचले इलाकों में पानी भर गया है।

स्पेशल खबर *ऑनलाइन गेमिंग कंपनी पर प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई...*

गेम्सक्राफ्ट की 1,906 करोड़ की संपत्ति कुर्क

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्ट से जुड़े धन शोधन मामले में 1,906 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क करने की जानकारी दी। एजेंसी का आरोप है कि कंपनी ने ऐसा ऑनलाइन खेल तंत्र विकसित किया, जिससे खिलाड़ियों में लगातार दांव लगाने की प्रवृत्ति बढ़ी और इसके माध्यम से बड़ी मात्रा में अवैध कमाई की गई।

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, यह कार्रवाई 22 जुलाई को धन शोधन निवारण अधिनियम के

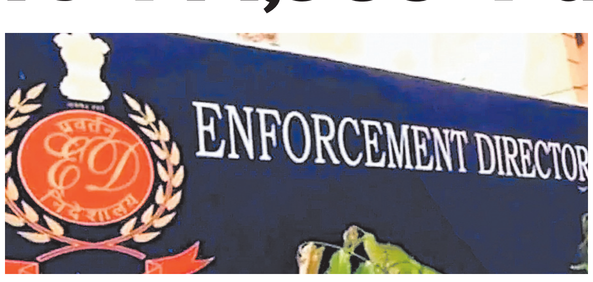

तहत की गई। जांच एजेंसी का कहना है कि कंपनी की गतिविधियों और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच के दौरान बड़ी मात्रा में ऐसी परिसंपत्तियों का पता चला, जिन्हें मामले से संबंधित माना गया है। इन्हें अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया गया है।

कुर्क की गई संपत्तियों में विभिन्न बैंक खातों में जमा धनराशि, सावधि जमा, पारस्परिक निवेश योजनाओं में निवेश, परिवर्तनीय ऋण पत्र, समता अंश, एक फार्महाउस तथा अनेक आवासीय और व्यावसायिक अचल संपत्तियां शामिल हैं। एजेंसी के अनुसार, ये परिसंपत्तियां गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के शेयरधारकों, उनके परिवार के सदस्यों, निजी पारिवारिक न्यासों तथा उनसे संबंधित विभिन्न संस्थाओं के नाम पर दर्ज हैं।

प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि कंपनी ने ऐसा गेमिंग वातावरण तैयार किया, जिसमें खिलाड़ियों को बार-बार दांव लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। एजेंसी का कहना है कि इस व्यवस्था के माध्यम से कंपनी ने बड़ी मात्रा में आर्थिक लाभ अर्जित किया। इसी आधार पर धन शोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है।

जांच एजेंसी ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कुर्क की गई परिसंपत्तियों को धन शोधन मामले की जांच का हिस्सा मानते हुए अपने नियंत्रण में लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय इस पूरे प्रकरण में वित्तीय लेनदेन, निवेश के स्रोत तथा संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की भूमिका की भी जांच कर रहा है।